

निजी कॉलेजों की तानाशाही पर भड़के छात्र और अभिभावक

छुट्टी के दिन आरोग्य भारती के कार्यक्रम में

जबरन भेजा, नहीं जाने वाले छात्रों को मिली सजा

भोपाल (ईएमएस)। अभिनव जैन कासलीवाल

राजधानी भोपाल के मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रों के साथ जबरदस्ती और अनुचित व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया है। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी के दिन, भोपाल के कई निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों ने छात्रों को आरोग्य भारती के मासिक प्रबोधन कार्यक्रम में जबरन भेजा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन द्वारा स्वास्थ्य जीवन शैली और जीवन प्रबंधन पर आधारित था।

कॉलेज प्रबंधन ने कार्यक्रम में उपस्थिति को जिओ टैगिंग के माध्यम से अनिवार्य कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की मंशा से छात्रों को बाध्य किया गया।

जो नहीं गए, उन्हें मिली मानसिक सजा

छुट्टी के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में जो छात्र शामिल नहीं हो सके, उन्हें कॉलेजों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमने सोचा था कि छुट्टी है, लेकिन कॉलेज ने जबरन बुलाया। जो नहीं गए,



उनकी पांच दिन की अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई। शनिवार को हाफ डे होने के बावजूद हमें पूरा दिन बैठा कर रखा गया और ऊपर से 140 पेज का असाइनमेंट भी थमा दिया गया। इसे डिस्प्लिन कहा जा रहा है, लेकिन यह तो सीधी प्रताड़ना है।

अभिभावकों ने जताई नाराजगी

छात्रों के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर अभिभावकों में भी जबरदस्त आक्रोश है। कई अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन के इस खैरिये को तानाशाही और विचारधारा थोपने की कोशिश करार दिया। उनका कहना है कि हमने बच्चों को पढ़ाई के लिए कॉलेज भेजा है, न कि किसी संगठन की सोच या विचारधारा थोपे जाने के लिए। छुट्टी के दिन इस तरह का दबाव अस्वीकार्य है।

महाकुंभ में भगवा रंग में रंगेगी

महाकाल की नगरी

सिंहस्थ के लिए शिप्रा के जल से उगाए 50 हजार बांस, संत लहराएं धर्मध्वजा

भोपाल, ईएमएस। भगवान महाकाल की नगरी उज्जयिनी सिंहस्थ में सनातन धर्मध्वजाओं से लहरा उठेगी। इसी भाव को लिए उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए 50 हजार बांस उगाए गए हैं, उद्देश्य यहीं है, शिप्रा के जल से सिंचित 30 फीट ऊंचे बांसों पर महाकुंभ में आने वाले साधु-संत और अखाड़े सनानत की धर्मध्वजाएं लहराए। सिंहस्थ में आने वाले सभी अखाड़े व साधुओं को उज्जैन में धर्मध्वजा लहराने के लिए 30 फीट ऊंचे बांस उज्जैन वन मंडल निशुल्क उपलब्ध कराएगा। वन विभाग ने भैरवगढ़ मार्ग पर शिप्रा नदी के किनारे 10.72 हेक्टेयर में बांस का जंगल उगाया है। सात साल से वन विभाग इनकी देखभाल कर रहा है जो 20 से 25 फीट ऊंचे हो चुके हैं व साल अमले दो सालों में

नदी किनारे 10.72 हेक्टेयर में बांस का जंगल

वन मंडल ने धार्मिक महत्त्व व को ध्यान में रख बांस उगाए हैं। इनकी देखरेख कर रहे डिप्टी रोजन अलित सैन बताते हैं कि नदी किनारे 10.72 हेक्टेयर में बांस का पूरा जंगल है जिसे शिप्रा नदी के जल से ही सिंचित किया गया है।

इनकी ऊंचाई 30 फीट से ज्यादा हो जाएगी। सिंहस्थ महापर्व के तीन महीने पहले इन बांसों की कटाई के बाद उन्हें व्यवस्थित कर वन मंडल कलेक्टर व मेला अधिकारी को सौंप देगा ताकि उनके माध्यम से सम्पूर्ण सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 13 अखाड़ों समेत जितने भी साधु-संत आए सभी को धर्म ध्वजा लहराने के लिए बांस भेंट किए जा सकें।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल खंडवा में कहा

ईमानदारी से काम होता तो

नदी - नाले खाली न होते

भोपाल, ईएमएस। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बार फिर कहा कि मेरे पास नाली, सीसी रोड, बाउंड्री वॉल और स्टाप डैम का पैसा मांगने मत आना। इस राज्य में इतने स्टाप डैम बने हैं कि मप्र के प्रत्येक नदी नाले के 50 मीटर पर स्टाप डैम बन जाना था। अगर ईमानदारी से काम हुआ होता तो आज कोई नदी नाले



खाली नहीं होते। ये साफ है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, उस पर कार्रवाई भी सख्ती से होगी। सोमवार को प्रहलाद पटेल खंडवा जिले पहुंचे। जहां उन्होंने किशोर कुमार भवन में आयोजित पंच-सरपंच सम्मलेन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पास नाली का पैसा मांगने मत आना, छठ रोड का पैसा मांगने मत आना, बाउंड्री

वॉल का पैसा मांगने मत आना और स्टाप डैम का भी पैसा मांगने मत आना। उन्होंने कहा कि अगर संख्या देखी जाए तो प्रदेश में इतने स्टाप डैम बने हैं कि प्रत्येक नदी नाले के 50 मीटर पर स्टाप डैम बन जाना था। मंत्री ने आगे कहा कि ईमानदारी से काम हुआ हो था आज कोई नदी नाले खाली नहीं होते। सभी में पानी होता। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि अब ग्राम पंचायतों को फंड की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का फोकस ग्राम पंचायतों पर है। इसलिए इस बार पंचायतों का बजट 14 सौ करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ कर दिया गया है। महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर पंच परमेश्वर की कल्पना की थी।

डिप्टी सीएम ने दिया आश्वासन

20 जिलों के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को 4 माह से नहीं मिली सैलरी

भोपाल, ईएमएस।

मप्र के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स और सविदा के माध्यम से करीब 32 हजार कर्मचारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन विभाग से उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही। प्रदेश के करीब 20 जिलों में चार से महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। इस कारण कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारियों ने 22 अप्रैल से राजधानी भोपाल में आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन एक दिन पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द ही सैलरी दी जाएगी।

इसके बाद कर्मचारियों ने 22 अप्रैल को होने वाली अपनी हड़ताल को टाल दिया है, लेकिन कर्मचारियों ने कहा है कि अगर 15 दिन की भीतर उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है तो वे हड़ताल करने को मजबूर होंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि प्रदेश में 32 हजार से अधिक आउटसोर्स



स्वास्थ्य कर्मचारी सपोर्ट स्टाफ, वार्ड बाय, आया, सुरक्षार्थी, डाटा एंट्री अपरेटर आदि के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कई कर्मचारी पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सविदा पर कार्य कर चुके हैं। कई जिलों में कर्मचारियों को 4-5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। कोमल सिंह ने कहा है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी सैलरी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गईं तो वे अनिश्चालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

राजनीतिक

प्रशासनिक

कौन थे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

यह कार्यक्रम आरोग्य भारती द्वारा समन्वय भवन, अपैक्स बैंक सभागार में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव ने की। प्रख्यात मैनेजमेंट गुरु एन. रघुरमन मुख्य वक्ता थे, और सारस्वत वक्ता के रूप में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉ. अशोक कुमार वाघ्पेय उपस्थित थे। आयोजन के निवेदक आरोग्य भारती के मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा और आरोग्य भारती के भोपाल महानगर अध्यक्ष डॉ. अभिजीत देशमुख थे।

मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप जरूरी

इस पूरे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शिक्षा संस्थान अब शैक्षणिक केंद्रों की जगह वैचारिक प्रचार के अड्डे बनते जा रहे हैं? छुट्टी के दिन छात्रों को किसी कार्यक्रम में जबरन भेजना, अनुपस्थिति पर सजा देना, और विचारधारा थोपना यह सब शिक्षा की मूल भावना के खिलाफ है। छात्रों, अभिभावकों और समाज के जागरूक नागरिकों ने शिक्षा विभाग और मानवाधिकार आयोग से इस पूरे मामले में तत्काल जांच और हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही, छात्रों पर लगाए गए सभी अनुशासनात्मक दंड को तुरंत रद्द किए जाने की आवश्यकता बताई है।



को काफी गंभीरता से लिया है। हम अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसान संघ से जुड़े किसानों, कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि रिपोर्ट तैयार करें।

किसान संघ अपने स्तर पर भी सभी प्रकार की जन संरचनाओं की गंभीर स्थिति को लेकर आर्य योजना तैयार कर रहा है। गांव गांव, कस्बे और शहरी कृषि क्षेत्र की सभी प्रमुख वाटर बॉडी को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं।

मप्र कांग्रेस ने संगठन मजबूती

को लेकर बनाया प्लान



भोपाल, ईएमएस। मप्र कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने संगठन की मजबूती के लिए रणनीति बनाई है। प्रदेश की 230 विधानसभाओं में प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधि होगा। एमपी प्रभारी हरीश चौधरी ने 15 दिन के अंदर प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पिछले दो महीने में प्रदेश के अलग-अलग संभागों का दौरा कर चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में लिए गए फैसलों पर अब अमल शुरू कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद प्रांतीय अधिवेशन की तैयारी भी की जा रही है। यह अधिवेशन संभवत - मई में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। जिसमें 2028 और 29 के चुनावों की रणनीति तय होगी।

मजदूर दिवस पर धरना देगा मप्र कर्मचारी मंच

भोपाल, ईएमएस। मप्र कर्मचारी मंच 1 मई मजदूर दिवस के दिन 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में विशाल धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा। इसी दिन अंशकालिक कर्मचारी अबेडकर मैदान में मुख्यमंत्री को खून से पोस्टकार्ड लिखेंगे। मप्र कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को रखाई कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं सुरक्षा श्रमिकों की हित की 9 सूत्रीय मांगों की समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है।

कांग्रेस का 40 दिवसीय संविधान

बचाओ अभियान 25 अप्रैल से

► राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर करेंगे रैली, फिर घर-घर जाकर देंगे दस्तक

भोपाल, ईएमएस।



कांग्रेस द्वारा मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान 25 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य स्तर, जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर रैली का आयोजन होगा। इसके बाद घर-घर जाकर दस्तक देकर कांग्रेस अपनी बात लोगों तक पहुंचाएगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केशी वेणुगोपाल द्वारा इस बारे में जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 19 अप्रैल को आयोजित की गई बैठक में इस अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की 22 अप्रैल की बैठक में इस अभियान को चलाने के लिए समन्वयक नियुक्त करने का फैसला लिया गया। कांग्रेस द्वारा जो रोडमैप बनाया गया है उसके अनुसार संविधान बचाओ अभियान के तहत सबसे पहले 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच राज्य स्तरीय संविधान

बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। इन रैली में केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर कमजोर किए जाने, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने, संसदीय प्रक्रिया को कमजोर करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को उठाया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को सभी को संबोधित करने के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद 3 मई से 10 मई तक जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। इन रैलियों में बेरोजगारी, महंगाई, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पतन, ग्रामीण संकट और कल्याणकारी नीतियों को कमजोर करने के मुद्दे को उठाया जाएगा। फिर 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। इस रैली को विधायक, विधानसभा उम्मीदवार, ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ स्तर के नेताओं द्वारा आयोजित किया जाएगा।

नेशनल हेराल्ड केस में मोदी-शाह ने

मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा प्रचार किया



मौजूद ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और देश को गुमराह करने के लिए भाजपा की साजिश है। ये सरासर एक राजनीतिक प्रतिशोध है। सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी

द्वारा दायर आरोपपत्र कुछ और नहीं बल्कि जनता का ध्यान बेरोजगारी, गिरती जीडीपी और सामाजिक अशांति से भटकाने, जनता को भ्रमित करने और बरगलाने के लिए गढ़ा गया एक झूठ है। शैलजा ने कहा कि आर्थिक संकट, लोगों के मुद्दों और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों- अमेरिका, चीन और बांग्लादेश से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यह कानूनी प्रतिशोध के अलावा कुछ और नहीं है।

सरकार ने ईडी को अपना विभाग बना लिया है

चुनिंदा ब्याज कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक ठगो है। प्रवर्तन निदेशालय को जवाब देना चाहिए कि एजेंसी ने ईडी के किसी सहयोगी या भाजपा नेता को क्यों नहीं हुआ। यह बदले की राजनीति, धमकी, उत्पीड़न और भय फैलाने की राजनीति है। हमें कितना भी चुप करावे की कोशिश करें, हम चुप नहीं होंगे। जो दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, वे खुद डरे हुए हैं। यह एक राजनीतिक साजिश है।

EMS ACADEMY OF JOURNALISM

(AFFILIATED BY BHARTIYA VIDYA BHAVAN, AHMEDABAD)

Become a Media professional

ADMISSION

OPEN FOR PG-DIPLOMA 2025

One Year Diploma Course

1. Journalism & Mass communication

2. Public Relation

3. Digital Media

4. Marketing & Sales management

APPLY NOW

Contact Us:

9302208608, 9229226533

www.emsindia.com, Jabalpur express.com

ems_academy@rediffmail.com

यदि आप बनाना चाहते हैं मीडिया की दुनिया में अपनी पहचान तो जुड़िये मध्यप्रदेश की नंबर 1 मीडिया एकेडमी से

Academy premises: Bhopal Teaching mode: Offline

FACILITIES

• Well equipped media lab & TV Studio

• Writing exercise for print and web

• Guidance by Media Professionals

• Practical Training of conducting Interview, Tv Reporting Writing Article, Field reporting etc.

• Regular Field Visits

• Well Qualified Faculty

• Guaranteed Internship and Placement

ADDRESS : 7, COMMERCIAL CHITTOD COMPLEX ZONE 1 M.P. NAGAR, BHOPAL MADHYA PRADESH